**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**उच्‍चतर शिक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 684**

**उत्तर देने की तारीखः 27.07.2015**

**केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी॰ए॰बी॰ई॰) के नामनिर्देशित सदस्यों के लिए मापदण्ड**

**684. श्री हरिवंशः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी॰ए॰बी॰ई॰) में नामित सदस्यों की नियुक्ति में किन मापदंडों को अपनाया जाता है;

(ख) एक ही विचारधारा के अधिकांश लोगों की नियुक्ति के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार देश की शिक्षा नीति में बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है और यदि हां, तो बदलाव के लिए किस स्तर पर शिक्षाविदों के सुझाव मांगे गये हैं?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्री

**(**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

**(क) और (ख): केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) को दिनांक 11.06.2015 के संकल्‍प के जरिए अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया है। सभी समूहों के हितों को ध्‍यान में रखते हुए निर्णयों को सुगम बनाने के लिए विभिन्‍न समूहों अर्थात् उद्योग, विशेष वर्गों (अनु. जाति/अनु. जनजाति/नि:शक्‍तजन), अल्‍पसंख्‍यक संस्‍थाओं और प्रसिद्ध शिक्षाशास्‍त्रियों, प्रौद्योगिकीविदों, वैज्ञानिकों, स्‍कूल शिक्षा/सृजनात्‍मक कलाओं/भाषाओं के विशेषज्ञों इत्‍यादि का प्रतिनिधित्‍व करने वाले सदस्‍यों को सीएबीई में नामित किया जाता है।**

**(ग): सरकार ने गुणवत्‍तापरक, नवाचार और शोध के संबंध में लोगों की बदलती हुई आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है जिसका उद्देश्‍य इसके विद्यार्थियों को आवश्‍यक कौशल और ज्ञान से सुसज्‍जित करके भारत को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्‍ति बनाना और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा उद्योग में श्रमशक्‍ति की कमी को दूर करना है। इसमें सभी हितधारकों जैसे कि शिक्षाविदों, अध्‍यापकों और सभी स्‍तरों के विद्यार्थियों को शामिल करके एक बहु-स्‍तरीय परामर्श प्रक्रिया का प्रस्‍ताव किया गया है। ऑनलाइन परामर्श प्रक्रिया** [**www.MyGov.in**](http://www.MyGov.in) **पोर्टल पर शुरू हो गई है और 33 अभिचिन्‍हित प्रकरणों के बारे में** [**www.MyGov.in**](http://www.MyGov.in) **पोर्टल पर बड़ी संख्‍या में सुझाव प्राप्‍त हो गए हैं। जमीनी स्‍तर पर यानि ब्‍लॉक के जरिए ग्राम पंचायत स्‍तर पर और जिले से लेकर राज्‍य स्‍तर पर परामर्श प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू किए जाने का प्रस्‍ताव है। इस संबंध में देश-भर से शिक्षाविदों से भी सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।**

\*\*\*\*\*